वॉल्यूम 33, सं. 4, अप्रैल, 2025

इंफोमेटिक्स

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा प्रकाशित एवं ई गवर्नेंस बुलेटिन

संपादकीय संयोजन : जी. वेंकू बाई

माननीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, श्री जितिन प्रसाद 18 फरवरी, 2025 को नई दिल्ली में प्रथम सीआईओ सम्मेलन के दौरान डिजिटल पहचान मैनुअल लॉन्च करते हुए।

MeitY ने सरकार की ऑनलाइन उपस्थिति को मानकीकृत करने के लिए डिजिटल ब्रांड पहचान मैनुअल का अनावरण किया

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने 18 फरवरी, 2025 को नई दिल्ली में मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ) सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण डिजिटल ब्रांड पहचान मैनुअल (डीबीआईएम) का अनावरण था, जो एक रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य पूरे भारत में सरकारी संस्थाओं की डिजिटल उपस्थिति को मानकीकृत करना है।

डीबीआईएम के मुख्य घटक

डीबीआईएम सरकारी प्लेटफॉर्म के लिए एकीकृत डिजिटल पहचान सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है। इसके मुख्य घटकों में शामिल हैं:

• **Gov.In कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम (CMS) प्लेटफ़ॉर्म:** यह प्लेटफ़ॉर्म वेबसाइट प्रबंधन को सुव्यवस्थित करता है, जिससे सरकारी पोर्टलों में स्थिरता और दक्षता सुनिश्चित होती है।

• **सेंट्रल कंटेंट पब्लिशिंग सिस्टम (सीसीपीएस):** कंटेंट गवर्नेंस के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली, प्रमुख सरकारी नीतियों, योजनाओं और पहलों को जनता के लिए आसानी से उपलब्ध कराती है, जिससे पारदर्शिता और जुड़ाव में सुधार होता है।

• **सोशल मीडिया अभियान दिशानिर्देश:** डिजिटल संचार को मानकीकृत करने के लिए स्थापित, ये दिशानिर्देश विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर सुसंगत और प्रभावी संदेश सुनिश्चित करते हैं।

सम्मेलन के दौरान, डीबीआईएम-अनुरूप एमईआईटीवाई वेबसाइट का अनावरण किया गया, जो एक सुसंगत और नागरिक-अनुकूल डिजिटल अनुभव का प्रदर्शन करती है।. इसके अतिरिक्त, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सहित पाँच अन्य मंत्रालयों की वेबसाइटों को नए दिशानिर्देशों के बाद और अधिक मानकीकृत और उपयोगकर्ता-अनुकूल अनुभव प्रदान करने के लिए नया रूप दिया गया है।

डीबीआईएम को राष्ट्रव्यापी रूप से अपनाने से नागरिक जुड़ाव में क्रांति आएगी, विश्वास मजबूत होगा और डिजिटल क्षेत्र में सरकारी सेवा वितरण में वृद्धि होगी। यह पहल प्रभावी शासन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है और डिजिटल रूप से सशक्त भारत के व्यापक दृष्टिकोण के साथ संरेखित है।

- अर्चना शर्मा, एनआईसी मुख्यालय

गुजरात और झारखंड की एनआईसी टीमों ने राज्य औषधि निदेशालय के साथ मिलकर एक्सएलएन परियोजना कार्यशाला का आयोजन किया

गुजरात और झारखंड की राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) टीमों ने झारखंड सरकार के राज्य औषधि निदेशालय के सहयोग से 3 मार्च 2025 को विस्तारित लाइसेंस, लैब और कानूनी नोड (एक्सएलएन) परियोजना पर केंद्रित एक कार्यशाला का आयोजन किया। यह पहल औषधि और प्रसाधन सामग्री विनियमन के क्षेत्र में अच्छे नियामक प्रथाओं को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

कार्यशाला में औषधि निरीक्षकों, लाइसेंसिंग प्राधिकारियों, संयुक्त निदेशकों और अन्य प्रमुख प्रतिभागियों सहित हितधारकों के विविध समूह को एक साथ लाया गया। इसका प्राथमिक उद्देश्य एक्सएलएन परियोजना में व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करना था, जिसमें नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और फार्मास्युटिकल क्षेत्र के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका पर जोर दिया गया।

एक्सएलएन परियोजना औषधि और प्रसाधन सामग्री विनियमन के क्षेत्र में अच्छे विनियामक अभ्यासों को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करती है। लाइसेंसिंग, प्रयोगशाला और कानूनी कार्यात्मकताओं को एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में एकीकृत करके, एक्सएलएन का उद्देश्य विनियामक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही को बढ़ाना है।

इस कार्यशाला का सफल आयोजन गुजरात और झारखंड की एनआईसी टीमों और झारखंड के राज्य औषधि निदेशालय के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को दर्शाता है। ऐसी साझेदारियां डिजिटल परिवर्तन पहलों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण हैं जो नियामक उत्कृष्टता और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ संरेखित हैं।

गुजरात और झारखंड की एनआईसी टीमों ने झारखंड सरकार के राज्य औषधि निदेशालय के सहयोग से एक्सएलएन परियोजना पर केंद्रित एक कार्यशाला का आयोजन किया।

एक्सएलएन परियोजना और झारखंड में इसके कार्यान्वयन के बारे में अधिक जानकारी के लिए इच्छुक पार्टियां आधिकारिक पोर्टल https://xln.jharkhand.gov.in/ पर जा सकती हैं।

- राजीव कुमार सिन्हा, झारखंड

पुडुचेरी के नागरिक आपूर्ति मंत्री ने ऑनलाइन राशन कार्ड सेवाओं पर प्रशिक्षण में एनआईसी और वीएलई की सराहना की

पुडुचेरी में नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने एनआईसी के सहयोग से हाल ही में 15 जनवरी 2025 को पुडुचेरी में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) से जुड़े ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) की डिजिटल क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। प्रशिक्षण का उद्देश्य वीएलई को ऑनलाइन राशन कार्ड सेवाओं के बारे में जागरूक करना था, जो केंद्र शासित प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

माननीय नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री पी.आर.एन. थिरुमुरुगन ने सभा को संबोधित करते हुए ऑनलाइन सेवाओं के विकास और कार्यान्वयन में एनआईसी टीम के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने डिजिटल डिवाइड को पाटने में वीएलई की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि राशन कार्ड आवेदन जैसी आवश्यक सेवाएं सभी नागरिकों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के लिए सुलभ हों।

एनआईसी अधिकारियों ने अनुप्रयोग के वर्कफ़्लो और कार्यात्मकताओं का विस्तृत प्रदर्शन किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि वीएलई ऑनलाइन राशन कार्ड सेवाओं का उपयोग करने में नागरिकों की सहायता करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। इस पहल से पारदर्शिता बढ़ने, प्रसंस्करण समय कम होने और राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया की समग्र दक्षता में सुधार होने की उम्मीद है।

वीएलई को आवश्यक ज्ञान और उपकरणों से सशक्त बनाकर, विभाग का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिक राशन कार्ड से संबंधित ऑनलाइन सेवाओं तक निर्बाध रूप से पहुँच सकें। यह प्रशिक्षण बेहतर प्रशासन और सेवा वितरण हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

माननीय नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री श्री पी.आर.एन. थिरुमुरुगन ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान ऑनलाइन सेवाओं के विकास और कार्यान्वयन में एनआईसी टीम के प्रयासों की सराहना की।

ऑनलाइन राशन कार्ड सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए नागरिक, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, पुडुचेरी के आधिकारिक पोर्टल पर जा सकते हैं।

- एन.एस. कुमारन, पुडुचेरी

जम्मू और कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जम्मू और कश्मीर आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया

माननीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 10 जनवरी, 2025 को जम्मू में सिविल सचिवालय में जम्मू और कश्मीर सूचना का अधिकार (आरटीआई) ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया, जो क्षेत्र के शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।

उद्घाटन कार्यक्रम में माननीय उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी, कैबिनेट मंत्री सकीना इटू, जावीद अहमद राणा, अहमद डार, मुख्य सचिव अटल डुल्लू, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव धीरज गुप्ता, प्रशासनिक सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

अपने संबोधन में माननीय मुख्यमंत्री ने पोर्टल विकसित करने में एनआईसी जम्मू और कश्मीर के प्रयासों की सराहना की, नागरिकों के लिए आरटीआई आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की इसकी क्षमता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "यह पहल आरटीआई अधिनियम के तहत सरकारी सूचनाओं तक आसान पहुंच प्रदान करेगी, नागरिकों को अधिक तेज़, अधिक पारदर्शी और लागत-कुशल तंत्र के साथ सशक्त बनाएगी।" मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल के व्यापक प्रचार का भी आह्वान किया ताकि जम्मू और कश्मीर के नागरिक इसके लाभों से अवगत हों।

एनआईसी जम्मू और कश्मीर द्वारा विकसित यह पोर्टल आरटीआई आवेदन प्रक्रिया को मैनुअल से ऑनलाइन में परिवर्तित करता है, जिससे नागरिक अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं, उनकी स्थिति पर नज़र रख सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं, जिससे सरकारी कार्यालयों में भौतिक रूप से जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

पोर्टल की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसमें आवेदकों को भविष्य के संदर्भ के लिए एसएमएस और ईमेल के माध्यम से पंजीकरण संख्या जारी की जाती है, जिससे आरटीआई आवेदनों पर आसानी से नज़र रखी जा सकती है।

पोर्टल 61 सरकारी विभागों, 272 नोडल अधिकारियों/सार्वजनिक प्राधिकरणों, 720 प्रथम अपीलीय अधिकारियों (एफएए) और 3,419 केंद्रीय को एकीकृत करता है।

माननीय मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला, माननीय उपमुख्यमंत्री श्री सुरिंदर कुमार चौधरी अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, जम्मू के सिविल सचिवालय में जम्मू-कश्मीर आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल के शुभारंभ समारोह की अध्यक्षता करते हुए।

केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) व्यापक कवरेज सुनिश्चित करते हैं और नागरिकों को सरकारी गतिविधियों के बारे में सूचित रखते हैं। यह पहल प्रशासन की सुलभ सूचना के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता के साथ तालमेल बिठाते हुए शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

- अनिल कुमार शर्मा, जम्मू और कश्मीर

एनआईसी ने ई-डीएआर के साथ पंजाब को सशक्त बनाया

सड़क सुरक्षा को बढ़ाने और दुर्घटना रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, एनआईसी ने परिवहन विभाग, पंजाब के सहयोग से 13 फरवरी 2025 को महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान (एमजीएसआईपीए), चंडीगढ़ में एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया, ताकि राज्य में इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ई-डीएआर) सॉफ्टवेयर के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके।

परिवहन मंत्री श्री लालजीत सिंह भुल्लर के मार्गदर्शन में संचालित यह पहल भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग और दावों के निपटान में सुधार के निर्देशों के अनुरूप है।

इस पहल के केंद्र में एनआईसी की ईडीएआर प्रणाली है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सड़क दुर्घटनाओं पर वास्तविक समय में डेटा संग्रह सुनिश्चित करता है। यह प्रणाली अधिकारियों को दुर्घटना डेटा को तुरंत कैप्चर करने, उसका विश्लेषण करने और साझा करने में सक्षम बनाती है, जिससे त्वरित प्रतिक्रिया समय और कुशल दावा निपटान की सुविधा मिलती है। एनआईसी विशेषज्ञों के नेतृत्व में आयोजित प्रशिक्षण सत्र में सरकारी अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और बीमा प्रतिनिधियों को ई-डीएआर का उपयोग करके निर्बाध डेटा प्रविष्टि और रिपोर्ट तैयार करने के बारे में व्यावहारिक प्रदर्शन प्रदान किए गए। राज्य परिवहन आयुक्त श्री जसप्रीत सिंह ने इस प्रौद्योगिकी-संचालित समाधान को विकसित करने और लागू करने में एनआईसी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईडीएआर प्रणाली दुर्घटना रिपोर्टिंग के पूरे कार्यप्रवाह को डिजिटल बनाती है, जिससे देरी कम होती है और पीड़ितों और उनके परिवारों को समय पर वित्तीय सहायता सुनिश्चित होती है।

सत्र के दौरान, राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी श्री विवेक वर्मा, सीजीएम एनआईसी दिल्ली श्री

एनआईसी के अधिकारी ने ई-डीएआर प्रणाली पर विस्तृत प्रस्तुति दी, जिसमें वास्तविक समय दुर्घटना रिपोर्टिंग और सुव्यवस्थित दावा निपटान के लिए इसकी विशेषताओं का प्रदर्शन किया गया।

जतिंदर कुमार, श्री नरिंदर सिंह और श्री पवन गुप्ता सहित एनआईसी अधिकारियों ने ई-डीएआर की कार्यक्षमताओं पर विस्तृत प्रस्तुतियाँ दीं। प्रशिक्षण में शामिल थे:

- सड़क सुरक्षा उपायों को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक दुर्घटना जांच तकनीकें।
- वास्तविक समय रिपोर्टिंग और नीति-निर्माण के लिए दुर्घटना डेटा डिजिटलीकरण।
- पीड़ितों के लिए चिकित्सा देखभाल में तेजी लाने के लिए कैशलेस उपचार प्रावधान।

- परमिंदर कौर, पंजाब

उत्तराखंड विधानसभा ने डिजिटल परिवर्तन को अपनाया

कागज रहित शासन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री और उत्तराखंड विधानसभा के माननीय अध्यक्ष ने 21 फरवरी 2025 को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) पोर्टल लॉन्च किया। नेवा पोर्टल, एक अत्याधुनिक डिजिटल विधायी समाधान है, जिसका उद्देश्य स्मार्ट और कुशल डेटा प्रबंधन प्रणाली प्रदान करके उत्तराखंड विधानसभा के कामकाज को सुव्यवस्थित करना है। डिजिटल रिकॉर्ड, विधायी कार्यवाही तक वास्तविक समय में पहुँच और एक स्वचालित वर्कफ़्लो को एकीकृत करके, नेवा भौतिक कागजी कार्रवाई की आवश्यकता को समाप्त करता है, जिससे विधानसभा का संचालन अधिक पारदर्शी, सुलभ और पर्यावरण के अनुकूल हो जाता है।

लॉन्च इवेंट में बोलते हुए, माननीय मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि नेवा कार्यकुशलता को बढ़ाकर, वास्तविक समय की सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करके और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देकर विधायी शासन में क्रांति लाएगा। माननीय अध्यक्ष ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह पहल डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि विधायक, अधिकारी और आम जनता विधायी दस्तावेजों, विधेयकों और रिपोर्टों तक सहजता से पहुँच सकें।

एनआईसी द्वारा विकसित नेवा प्लेटफॉर्म को पूरे देश में विधायी कार्यवाही को डिजिटल और स्वचालित बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह वास्तविक समय में दस्तावेज़ एक्सेस, इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रोसेसिंग, समिति प्रबंधन और डिजिटल वोटिंग को सक्षम बनाता है, जिससे प्रशासनिक देरी में काफी कमी आती है।

उत्तराखंड द्वारा नेवा को अपनाने के साथ, राज्य उन विधानसभाओं की बढ़ती सूची में शामिल हो गया है, जिन्होंने कागज रहित शासन की ओर कदम बढ़ाया है, जिससे विधायी प्रक्रियाएँ अधिक

उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री और उत्तराखंड विधानसभा के माननीय अध्यक्ष ने विधायी दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एमईआईटीवाई के तहत एनआईसी द्वारा एक डिजिटल पहल नेवा पोर्टल का उद्घाटन किया।

कुशल, पारदर्शी और डिजिटल रूप से समावेशी बन गई हैं। यह पहल डिजिटल हस्तक्षेपों के माध्यम से शासन को आधुनिक बनाने के लिए एक बेंचमार्क स्थापित करती है, जो ई-गवर्नेंस और स्मार्ट विधायी प्रथाओं के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है।

- राजीव जोशी, उत्तराखंड

एनआईसी ने सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2025 मनाया

एनआईसी ने अपने राज्य और जिला केंद्रों में डिजिटल सुरक्षा, साइबर स्वच्छता और जिम्मेदार इंटरनेट उपयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2025 मनाने में सक्रिय रूप से भाग लिया। 13 फरवरी को मनाई जाने वाली इस वार्षिक वैश्विक पहल का उद्देश्य व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारी एजेंसियों के लिए एक सुरक्षित, अधिक समावेशी डिजिटल वातावरण को बढ़ावा देना है।

इस अवसर पर, एनआईसी की राज्य और जिला टीमों ने साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यशालाएँ, इंटरैक्टिव सत्र और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया गया:

- फ़िशिंग, मैलवेयर और पहचान की चोरी जैसे साइबर खतरों को पहचानना।
- डेटा सुरक्षा और सुरक्षित ऑनलाइन लेनदेन के लिए सर्वोत्तम अभ्यास।
- ज़िम्मेदार इंटरनेट उपयोग और डिजिटल पहचान की सुरक्षा।
- साइबर सुरक्षा और डिजिटल गोपनीयता पर सरकारी पहल।

एनआईसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने आज के डिजिटल युग में साइबर लचीलेपन के महत्व पर जोर दिया, खासकर संवेदनशील नागरिक डेटा को संभालने वाली सरकारी एजेंसियों के लिए।

एनआईसी पूरे देश में सुरक्षित डिजिटल शासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस समारोह के हिस्से के रूप में, एनआईसी विशेषज्ञों ने संगठन की प्रमुख पहलों पर प्रकाश डाला, जिनमें शामिल हैं:

- ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों में साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना।
- ई-प्रमाण और डिजीलॉकर के माध्यम से सुरक्षित प्रमाणीकरण तंत्र को बढ़ावा देना।
- सुरक्षित डिजिटल प्रथाओं पर सरकारी कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाना।

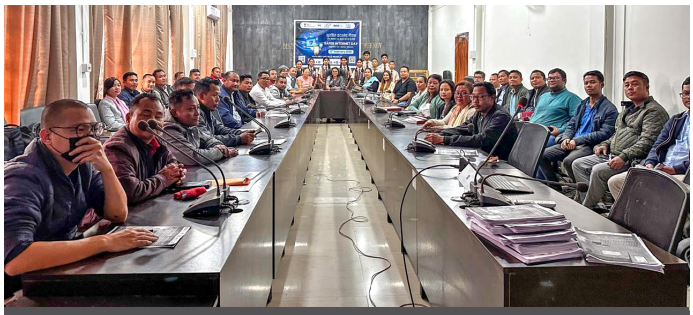

मेघालय में सुरक्षित इंटरनेट दिवस सत्र आयोजित किए गए, ताकि साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके, डिजिटल रूप से सशक्त समाज के लिए सुरक्षित और जिम्मेदार इंटरनेट प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा सके।

एनआईसी अधिकारियों ने साइबर धोखाधड़ी को रोकने में नागरिक जागरूकता के महत्व को भी दोहराया, विशेष रूप से बढ़ते डिजिटल लेनदेन और ऑनलाइन सेवा अपनाने के मद्देनजर।

कागज़ रहित शासन और डिजिटल परिवर्तन की ओर बढ़ते बदलाव के साथ, सुरक्षित इंटरनेट दिवस जैसी पहल साइबर-जागरूक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्य-व्यापी जागरूकता कार्यक्रमों और सक्रिय साइबर सुरक्षा उपायों के माध्यम से, एनआईसी एक सुरक्षित, डिजिटल रूप से सशक्त भारत सुनिश्चित करने में एक प्रेरक शक्ति बनी हुई है।

- अर्चना शर्मा, एनआईसी मुख्यालय

देशभर में ई-शासन गतिविधियों के बारे मे नवीनतम व अद्यतन समाचारों व सूचना के लिये News पर जाये https://informatics.nic.in/news